



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 1986/फाल्गुन 29, 1907

No. 66]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 1986/PHALGUNA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1986

संकल्प

सं. 14016/1/77-पी सी 3 :—हाल ही में देश में प्लास्टिक सामग्री की उपलब्धि में काफी वृद्धि हुई है और भावी उत्पादन योजनाओं से देश में अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक रेजिनों की उपलब्धि होने की संभावना है। संसार में तेजी से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है और प्लास्टिकों ने सामग्री तथा ऊर्जा के संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख उपाय के तौर पर भारत सरकार कृषि और मिट्टी में प्लास्टिकों के उपयोग बढ़ाने और विकसित करने के लिए विचार कर रही है। तदनुसार मार्च, 1981 में कृषि में प्लास्टिकों में उपयोग विषयक राष्ट्रीय समिति (एन सी पी ए) का गठन किया गया था। अब से राष्ट्रीय समिति ने एक विचार-पूर्ण योजना के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ताकि राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार और दूसरे संगठन राष्ट्रीय समिति की

विभिन्न सिफारिशों पर अमल करे। राष्ट्रीय समिति का नीचे
लिखे अनुसार पुनर्गठन किया गया है :—

1. डा. जी. बी. के. राव,
भूतपूर्व सदस्य,
योजना आयोग —अध्यक्ष
2. महानिदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली —सदस्य
3. श्री एल. एन. बोषी
संयुक्त सचिव
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली —सदस्य
4. निदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली —सदस्य

5. संयुक्त सचिव,
सिंचाई विभाग,
नई दिल्ली —सदस्य
6. संयुक्त सचिव (विस्तार),
कृषि विभाग,
नई दिल्ली —सदस्य
7. सदस्य,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली —सदस्य
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
इंडियन पेट्रोकीमिकल्स
कारपोरेशन लि.,
डाकबोर पेट्रो-कीमिकल्स, बडोदरा सदस्य

सरकार ज्यादा से ज्यादा ऐसे तीन गैर-सरकारी सदस्य भी नामित कर सकती है जो उपयोग-कर्ताओं और/अथवा उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों।

2. समिति नीचे लिखे विषयों पर विचार करेगी :—

1. निश्चित अवधि में विविध स्थानों पर पर्याप्त प्लास्टिकलम्बर विकास केन्द्रों की स्थापना करके एक केन्द्रीय समन्वय कक्ष के जरिए उन केन्द्रों के परिचालनों पर नजर रखी जाए, यह सुनिश्चित करना।
2. प्लास्टिकलम्बर विकास केन्द्रों में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर पूरे देश में प्लास्टिकलम्बर के अधिक विकास पर नजर रखना और उसे प्रोत्साहन देना।
3. प्लास्टिकलम्बर परिचालनों में उपयोग में लिए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित किए जाए, यह सुनिश्चित करना।
4. प्लास्टिक के कच्चे माल के उपयोग के लिए भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में नई-नई उपयोगिताओं के गहन अभ्ययन की समय-समय पर सहायता देना।
5. समय-समय पर सरकार के विचारार्थ नीति-विषयक मामले, राजस्व शुल्क संशोधन, प्लास्टिकलम्बर उपयोगों के लिए नीचे के स्तर पर कच्चे माल और तैयार उत्पाद की उपलब्धता आदि जैसे प्रश्नों के बारे में सिफारिश करना जिससे कि कृषि में प्लास्टिकों का उपयोग बढ़े और जो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के व्यापक हित में हो
6. राज्य स्तर की समितियों के कार्यकलापों को सक्रिय बनाना और सहभागिता की उचित भावना सुनिश्चित करना तथा जानकारी और सहभागिता का आदान प्रदान करना।
7. प्लास्टिकलम्बर उपयोगों के लिए प्लास्टिक सामग्रियों के वितरण चैनलों के बारे में सरकार को सिफारिश करना।
3. प्रारम्भ में समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा। समिति आवश्यकतानुसार बार-बार मिलेगी लेकिन हर तीन महीने में एक बार अवश्य मिलेगी। समिति अपना कार्यकाल सम्पन्न होने पर अपनी रिपोर्ट देगी लेकिन उसे जरूरत के अनुसार बार-बार अन्तरिम रिपोर्टें भी देनी चाहिए।
4. समिति को सचिवालयीन सहायता इस प्रयोजन के लिए गठित केन्द्रीय समन्वय कक्ष से दी जाएगी।
5. गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित संगठनों द्वारा उठाया जाएगा। सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सम्बन्धित, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग देंगे। समिति का अन्य खर्च रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग तथा आई. पी. सी. एल. द्वारा वहन किया जाएगा।
6. सरकार यदि जरूरी हो तो, समिति के गठन में उचित परिवर्तन कर सकती है।

एल. एन. दोषी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

New Delhi, the 20th March, 1986

RESOLUTION

No. 14016/1/77-PC.III.—The availability of plastics materials in the country has increased substantially recently and the future plans of production are likely to make available very large quantities of plastics resins in the country. The use of plastics in the world has increased rapidly and has acquired special significance in the conservation of material, energy and has contributed greatly to increase production of agriculture produce. The Government of India has been considering the promotion and development of uses of plastics in agriculture and irrigation as a major step in improving agricultural yields and efficiencies. Accordingly a National Committee on the Use of Plastics in Agriculture was constituted in March 1981. The National Committee has since submitted its reports with a prespective plan to implement the various recommendations of the National Committee by the State Governments, Central Government and other organisations. The National Committee has been reconstituted as under :—

1. Dr. G.V.K. Rao —Chairman
Former Member,
Planning Commission.
2. Director General, —Member
Indian Council of Agricultural
Research, New Delhi.
3. Shri L.N. Doshi, Member
Joint Secretary,
Department of Chemicals
and Petrochemicals,
Ministry of Industry,
New Delhi.
4. Director, —Member
Indian Agricultural Research
Institute, New Delhi.

- | | | |
|----|--|--------|
| 5. | Joint Secretary,
Department of Irrigation,
New Delhi. | Member |
| 6. | Joint Secretary (Extension),
Department of Agriculture,
New Delhi. | Member |
| 7. | Member
Central water Commission,
New Delhi. | Member |
| 8. | Chairman & Managing Director,
Indian Petrochemicals Corpn. Ltd.
PO Petrochemicals, Baroda. | Member |

The Government may also nominate not more than three non-official Members representing the interest of the users and/or the industry.

2. The terms of reference of the Committee would be as follows :—

- (i) To ensure establishment of adequate Plasticulture Development Centres (PDCs) at various Centres within schedule and to monitor their operations through the Central Coordination Cell.
- (ii) To monitor and stimulate further the development of plasticulture throughout the country based on the work to be carried out at PDCs.
- (iii) To ensure setting up of quality standards for plastic products used in plasticulture operations.
- (iv) To suggest from time to time in depth studies on newer applications in agricultural sector under Indian conditions using plastic raw materials.

(v) To recommend to Government from time to time issues for consideration such as policy matters, fiscal duty structure revision, availability of raw material for plasticulture application and finished product at grass root level, etc. which can extend the use of plastics in agriculture and are in the overall interest of national economy.

(iv) To reactivate State level Committees functioning and to ensure greater sense of participation as well as cross exchange of information and participation.

(vii) To recommend to Government on distribution channels of plastic materials for plasticulture applications to the grass root level.

3. The term of the Committee will be initially for a period of five years. The Committee shall meet as often as necessary but at least once a quarter. The Committee will submit its Report at the end of its terms, but it should submit interim reports as often as necessary.

4. The secretarial assistance required for the Committee will be provided by the Central Coordination Cell constituted for the purpose.

5. The expenditure on TA/DA of the non-official Members will be met by concerned organisations. The TA/DA of the Government officials will be met by the concerned administrative Ministries/Department. The other expenditure on the Committee will be borne by the Department of Chemicals & Petrochemicals and IPCL.

6. Government may make suitable changes in the constitution of the Committee, if required.

I. N. DOSHI, Jt. Secy.